किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि? विश्वासघात और दोबारा धोखा!

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, भाजपा और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने का देश के किसानों से वायदा किया था। लेकिन, कई अन्य वायदों की तरह ही, यह भी एक 'जुमला' ही बन गया है।

2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने, स्वामीनाथन समितियों की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का पहले से ही भुगतान होने की घोषणा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। अब भाजपा सरकार ने फिर से एमएसपी पर एक और भ्रामक घोषणा की। 4 जुलाई 2018 को, वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा बहुत अधिक जोर–शोर से की गई कि यह लागत में 50% जोड़कर है। इसे 'ऐतिहासिक' भी बताया गया। उसी दिन, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने इसकी किसानों के साथ 'ऐतिहासिक विश्वासघात' के रूप में निंदा की।

सरकार ने ए2+एफएल के रूप में लागत की गणना की जहाँ ए2 किसानों द्वारा बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई, किराए पर श्रम, किराए पर मशीनरी आदि जैसे इनपुट के लिए जेब से खर्च करना है और एफएल अवैतनिक पारिवारिक श्रम की लागत के लिए है।

लेकिन स्वामीनाथन समिति ने सी2 के रूप में व्यापक लागत की सिफारिश की जिसमें ए2+एफएल+किराए पर/अपनी जमीन और निश्चित पूंजी पर ब्याज शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि माल और सेवाओं के औद्योगिक उत्पादन की लागत में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम शामिल हैं।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के आयोग की गणना के मुताबिक सरकार द्वारा घोषित एमएसपी और वास्तविक राशि के बीच बहुत अंतर है यदि यह नीचे दिखाए गए स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर आधारित होता।

फसल	ए 2+एफएल प्रति क्विंटल	सी2 प्रति क्विंटल	एमएसपी (2018–19) प्रति क्विंटल	सी2+50%	सी2+50% और एमएसपी में अंतर प्रति क्विंटल
	वर्ष 2018–19 के लिए सीएसीपी लागत				
धान	1166	1560	1750	2340	-590.0
ज्वार हाइब्रिड	1619	2183	2430	3274.5	-844.5
बाजरा	990	1324	1950	1986	-33.0
रागी	1931	2370	2897	3555	-658.0
मक्का	1131	1480	1700	2220	-520.0
अरहर	3432	4981	5675	7471.5	-1796.5
मूंग	4650	6161	6975	9241.5	-2266.5
उड़द	3438	4989	5600	7483.5	-1883.5
मूंगफली	3260	4186	4890	6279	-1389
सूरजमुखी के बीज	3592	4501	5388	6751.5	-1363.5
सोयाबीन	2266	2972	3399	4458	-1059.0
तिल	4166	6053	6249	9079.5	-2830.5
काला तिल	3918	5135	5877	7702.5	-1825.5
कपास	3433	4514	5150	6771	-1621.0

(एआईकेएस के बयान से)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा घोषित बढ़े हुए एमएसपी के आधार पर, किसानों को सभी खरीफ फसलों पर 590 रुपये से 1825.5 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार, किसानों को भारी मुनाफे के बारे में भाजपा सरकार का दावा जनता के साथ कुल मिलाकर धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है।

केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के कृषि विभागों द्वारा लागत गणना में भी बड़ी असमानता है। केंद्र द्वारा निर्धारित लागत बहुत ही कम है। दोनों ही किसानों की वास्तविक लागत से कम ही हैं। राज्य सरकारों द्वारा उनकी लागत गणना के आधार पर सिफारिश की गयी एमएसपी, केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की तुलना में काफी अधिक है।

इसके अलावा, सरकार ने खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पूरे देश में सुनिश्चित खरीद के बिना, एमएसपी के बारे में ऐसी कोई घोषणा केवल दिखावा ही है। सार्वजनिक खरीद केवल धान और गेहूं जैसी कुछ फसलों के लिए हो रही है। यहाँ तक कि यह भी कुल उत्पादन का 20% से कम ही है। अधिकांशतः अन्य फसलों की ज्यादातर राज्यों में कोई खरीददारी नहीं है।

खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के बारे में प्रधान मंत्री मोदीनीत भाजपा सरकार का लम्बा–चौड़ा दावा जनता के साथ ठगी और धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह के धोखे को उजागर करने की जरूरत है। देश भर के किसान लाभकारी कीमतों पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लड़ रहे हैं।

किसानों, विशेष रूप से गरीब और मध्यम किसानों, मजदूरों की तरह, नवउदारवादी व्यवस्था के तहत बदतर हालात का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के तहत नवउदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद से पिछले दो दशकों के दौरान 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मजदूरों और किसानों को इस नवउदारवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आना का यही समय है, जिसके तहत बड़े देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् के मुनाफों को बढ़ाने के लिए, मेहनतकशों पर भारी बोझ डाला जा रहा है।

5 सितंबर 2018 को 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' इन नीतियों को उलटने की मांग करने के लिए है। सरकारों को यह चेतावनी देना है कि मेहनतकश जनता के साथ इस तरह की ठगी और धोखाधड़ी को और सहन नहीं किया जा सकता है।

एकजुट हों! संघर्ष करो!

- *0.01 प्रतिशत के लिए काम करने वाली सरकार नहीं*
- *99.9 प्रतिशत के फायदे की नीतियों के लिए*